जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 307 प्रभात बीकानेर, शुक्रवार 30 मई, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

'पाकिस्तान की सेना सुनियोजित तरीके से प्रजातंत्र को खत्म कर रही है'

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो जेल में हैं, ने एक वक्तव्य जारी करके यह कहा है कि ''पाकिस्तान की सेना ने चुनाव जीत कर आयी सरकारों को केवल एक ''रबड़-स्टाम्प'' संस्थान बना दिया है, जिसे वे ''रिमोट कंट्रोल'' से चलाते हैं''

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो वर्तमान में जेल में हैं और जिनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, ने एक बार फिर देश की सर्वशक्तिमान सैन्य व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सेना पर ''व्यवस्थित रूप से लोकतंत्र को नष्ट करने'' और ''राजनीतिक व्यवस्था को अपने हितों के लिए हाइजैक करने'' का आरोप लगाया है।

अपने नवीनतम बयान, जो उनकी कानूनी टीम के माध्यम से जारी किया गया और पाकिस्तानी तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कुछ हिस्सों में प्रकाशित हुआ है, में खान ने आरोप लगाया कि सेना, खासकर रावलपिंडी में तैनात शीर्ष नेतृत्व, ने ''निर्वाचित सरकारों को महज रबर स्टैम्प बना दिया है'' और पाकिस्तान के लोकतंत्र को ''एक नियंत्रित शासन में बदल दिया है, जो रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है।''

- यह एक अजीबोगरीब बात है कि 2018 के आम चुनाव में इमरान खान को पाकिस्तान में चहेता उम्मीदवार माना जाता था और वे चुनाव जीते तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, सेना की पूरी मदद से।
- पर, 2022 तक इमरान खान व सेना के रिश्ते खट्टे हो चुके थे, विदेश नीति व सेना के उच्च अफसरों की नियुक्ति के सवाल पर तथा इमरान का खुला आरोप है कि सेना ने प्रायोजित अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको हटवा दिया था।
- इमरान खान इसी लय में यह साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सच्चा प्रजातंत्र तभी संभव है, जब सेना ''बैरैक्स'' में लौट जाए और अपनी भूमिका संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं तक ही सीमित रखे।
- इमरान खान का यह ''हृदय परिवर्तन'' कैसे हुआ और क्यों हुआ?
- इमरान खान पहले तो सेना की मदद से प्र.मंत्री बने थे और अब सेना की भूमिका को ही बदलना चाहते हैं।
- पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक स्थिति का गहराई से विश्लेषण करने वाले प्रतिष्ठित विचारक के अनुसार, पहले तो इमरान खान ने सेना को मजबूत किया व सेना की भूमिका का पूर्ण समर्थन किया और पाकिस्तान की राजनीति में सेना को पैर जमाने का पूरा मौका दिया और अब वे पूर्णतया सेना की भूमिका को पाकिस्तान की गड़बड़ स्थिति के लिए जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं।

विडम्बना है कि कभी इमरान को सेना का पसंदीदा उम्मीदवार माना जाता था, विशेष रूप से 2018 के विवादास्पद आम चुनाव में, जिसमें उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को सत्ता मिली थी। 2022 में विदेश नीति और सैन्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाभियोग चलेगा जस्टिस वर्मा पर?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस यशवंत वर्मा पर जल्द ही महाभियोग की तलवार लटक सकती है। महाभियोग संसद में लाया जाएगा, जो किसी मौजूदा न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र उपाय है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक गोपनीय जाँच रिपोर्ट, जिसे इंडिया टुडे ने खोज निकाला है, में न्यायाधीश के घर के अंदर जली हुई नकदी के ढेर पर कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं मिला है। गलत आचरण के गंभीर आरोपों, संदिग्ध आग लगने के दौरान देर रात के फोन और दिल्ली पुलिस द्वारा कानूनी अड़चनें बताए जाने के साथ, अब केन्द्र और संसद पर दबाव है।

मानसून सत्र नज़दीक आ रहा है,

- सुप्रीम कोर्ट की गोपनीय जाँच रिपोर्ट, जिसे इंडिया टुडे ने खोज निकाला है, के अनुसार, जस्टिस वर्मा अपने आवास पर आग लगने के बाद मिले जले हुए नोटों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके, इसलिए उन पर संसद में महाभियोग चलाने की कार्यवाही की जा सकती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्यसभा की आठ रिक्त सीटों पर चुनाव हैं, 19 जून को

इन चुनावों का गणना की दृष्टि से कुछ भारी असर नहीं पड़ेगा, राज्यसभा के राजनीतिक समीकरणों पर, लेकिन, एनडीए को थोड़ा नुकसान तो होगा ही इस चुनाव से

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मई। राज्यसभा की 8 रिक्त सीटों पर 19 जून को चुनाव होगा, इनमें से 6 सीटें तमिलनाडु से हैं और 2 असम से, हालांकि इनके नतीजों से राज्यसभा के सत्ता संतुलन पर खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए को मामूली झटका लग सकता है, खासकर तमिलनाडु में जहाँ बदलते राजनैतिक समीकरणों से गठबंधन को कई सीटों का नुकसान हो सकता है।

तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन का बहुमत हे। उसके पास 133 सीटें है, उसे कांग्रेस (17 सीट), वीसीके (4 सीट) और वामपंथी दल (3 सीट) का समर्थन भी प्राप्त है। इसके विपरीत अन्नाद्रमुक के पास 66, भाजपा के पास 4, पीएमके के पास 3 सीटें है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 34 वोट चाहिए और इस प्रकार द्रमुक को अधिकांश सीटें जीतने की उम्मीद है।

एनडीए के पास अभी राज्यसभा में 128 सीटें हैं और अगर तमिलनाडु में एनडीए 3-4 सीटें हार जाता है तो इसकी सीटों की संख्या में चार की कमी आ जाएगी। एनडीए की सीटों में यह कमी इंडिया गठबंधन का मनोबल बढ़ा सकती है। जिसकी सीटें 84 से बढ़कर 89 हो सकती हैं। हालांकि, गैर भाजपा, गैर कांग्रेसी दलों की सीटें 20 ही रहेगी।

असम में मुकाबले के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ राज्य विधानसभा में 126 सीटें हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 42 वोटों की जरुरत होगी। यह से एनडीए के दो सदस्य बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य (असम गण परिषद) और भाजपा के कामाख्या प्रसाद तासा 4 जून को रिटायर हो रहे हैं। यहाँ भाजपा के लिए दोनों सीटों पर कब्जा कायम रखना मुश्किल हो

- इस चुनाव में 6 सीटें तमिलनाडु में भरी जायेंगी तथा भाजपा व अन्नाद्रमुक गठबंधन के पास चार सीटें कम हैं अपना उम्मीदवार जिताने के लिए। अतः, भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन को कोई खास राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है।
- आसाम में जो दो सांसद रिटायर हो रहे है वे दोनों एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं। पर, आसाम में भाजपा को जितने वोट चाहिये अपना उम्मीदवार जिताने के लिए, उसमें चार विधायकों की कमी है। अतः भाजपा (एनडीए) को दो सीटों का नुकसान हो सकता है।
- इंडिया गठबंधन की राज्यसभा की सीट संख्या में शायद इज़ाफा नहीं हो, पर, अगर आसाम में भाजपा (एनडीए) दो सीटें हार जाती है तो इंडिया गठबंधन के मनोबल को जरूर मजबूती मिलेगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जासूसी के संदेह में पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का निजी सचिव गिरफ्तार

निजी सचिव सरकारी कर्मचारी है, वह विभाग को बताये बिना पाकिस्तान यात्रा पर गया था

जैसलमेर, 29 मई (नि.सं.)। जैसलमेर में पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सचिव शकूर खान को जासूसी के शक में सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है।

वर्तमान में शकूर खान मंगलिया जिला रोजगार कार्यालय में क्लर्क है। उस पर आरोप है कि वह अपने विभाग को बिना बताए पाकिस्तान की यात्रा पर गया था। शकूर खान मंगलियों की ढाणी, बड़ोडा गांव का निवासी है। वह 2008 में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद के निजी सहायक के तौर पर काम कर चुका है। उस वक्त सालेह मोहम्मद पोकरण से विधायक थे।

शकूर को बुधवार को रोजगार कार्यालय से सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा। उससे पाकिस्तान यात्रा को लेकर पूछताछ की गई। जैसलमेर में पूछताछ के बाद रात को उसे जयपुर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए उससे जयपुर में सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी।

- सुरक्षा एजेन्सियों ने उसे जिला रोजगार कार्यालय से पकड़ा और रात को पूछताछ के लिये जयपुर ले गई।
- बताया जा रहा है कि निजी सचिव शकूर खान जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है।

शकूर की इस संदिग्ध गतिविधि के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने उसे डिटेन किया है। शकूर सरकारी कर्मचारी है, इसके बावजूद, वह विभाग को सूचना दिए बिना पाकिस्तान गया था, उससे इस बारे में पूछताछ की जा रही है।

शकूर खान से संयुक्त जांच कमेटी ने गहन पूछताछ की। बताया जा रहा है कि शकूर ने जांच में सहयोग नहीं किया।

दरअसल, भारत-पाक सीमा के नजदीक होने के कारण, जैसलमेर संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। फिलहाल इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री के निजी सचिव (पीए) की पाकिस्तान यात्रा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गुरुवार को उदयपुर प्रवास के दौरान राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री के निजी सचिव की पाक यात्रा का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस मामले में गहन जांच होगी और इसमें संलिप्त सभी लोगों की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एक मंत्री का पीए, जिसके पास प्रशासन और सरकार की अनेक जानकारियां होती हैं, अगरदुश्मन देश पाकिस्तान की यात्रा करता है, तो यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खनन पट्टों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना के लिए जाँच कमेटी बनेगी

जयपुर, 29 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी का गठन करे, यह कमेटी देखेगी की बजरी खनन पट्टा देने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना हुई है या नहीं? इसके अलावा, कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने की रिपोर्ट देने पर ही संबंधित व्यक्ति को खनन पट्टा जारी किया जाएगा। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. बृजमोहन सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में वीरेन्द्र लोढा ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बजरी लीज धारक वेलफेयर सोसायटी

- हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जाँच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही खनन पट्टा जारी होगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बार-बार अनुबंधन होते हैं, पर, सामान (हथियार) नहीं आता'

वायुसेना अध्यक्ष अमर प्रीत सिंह ने चौंकाने व हिलाने वाली टिप्पणी की सेना को हथियार पहुंचाने में हो रहे विलम्ब पर

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मई। इंडियन एयर फोर्स (आईएएफ) चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने उस समय एक धमाका ही कर दिया, जब उन्होंने रक्षा -खरीद के निर्धारित समय पर पूरा होने में विलम्ब पर सवाल खड़े कर दिये। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुये कहा कि हथियार -तन्त्र के उत्पादन में विलम्ब के कारण अधिकांश कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं हो पाते।

आज सीआईआई ऐनुअल बिज़नेस समिट में बोलते हुये, आईएएफ चीफ ने, विशेष रुप से स्वदेशी रक्षा प्रोजेक्टों में हुये विलम्ब के अनेक प्रकरणों का जिक्र किया।

शीर्ष आईएएफ ऑफिसर ने अफसोस व्यक्त करते हुये कहा कि हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने 83 तेजस एमके 1 ए, जो 4.5 जनरेशन लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट (एलसीए) है, में से एक भी एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि फरवरी, 2021 में 48000 करोड़ रु. के कॉन्ट्रैक्ट के पीएसयू अवार्ड के बाद, मार्च, 2024 में इनकी डिलीवरी शुरु होने की उम्मीद थी।

इस मामले में एचएएल दोषी भले ही दिखाई दे रही हो, लेकिन तथ्य यह है कि एचएएल का उत्पादन ''जनरल इलेक्ट्रिक'' की ओर से इंजनों की धीमी डिलीवरी से प्रभावित हो रहा है, और इसके पीछे कारण यह है कि इस अमेरिकन फर्म को सप्लाई चेन की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, ''तेजस एमके 1 की डिलीवरी में विलम्ब हुआ है। तेजस एमके 2 का प्रोटोटाइप अभी तक सामने नहीं आया है। गोपनीय एएमसीए फाइटर का प्रोटोटाइप अभी तक है ही नहीं।

- वायु सेना अध्यक्ष ने विशेष रुप से देशी हवाई कम्पनियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, ''युद्ध जीतने के लिये, सेना को सुदृढ़ होना जरुरी है।''
- उन्होंने तेजस लड़ाकू विमान का उदाहरण दिया। 2021 में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 48,000 करोड़ का अनुबंधन हुआ था, तेजस विमान के निर्माण व सप्लाई के लिये, 83 विमान मार्च, 2024, तक प्राप्त होने थे, वायु सेना को, पर अभी तक यह सप्लाई नहीं आई है।

ज्ञातव्य है कि समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच सहयोग पर जोर देते हुये, आईएएफ चीफ ने भारत में वैपन सिस्टम्स की डिज़ाइनिंग की आवश्यकता बताई तथा उन्होंने सशस्त्र सेनाओं तथा उद्योग के बीच विश्वास एवं पारदर्शिता विकसित किये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, ''हम भारत में उत्पादन किये जाने के बारे में बात नहीं कर सकते, हमें डिज़ायनिंग के बारे में बात करने की जरुरत है। हमें जरुरत इस चीज की है कि सेनाओं और उद्योग के बीच विश्वास पैदा हो। हमें पूरी तरह खुला रहने की, पारदर्शिता की जरुरत है। अगर हमने किसी चीज के लिये वचन दे दिया है, तो हमें उसे पूरा करना चाहिये। एयर फोर्स भारत में निर्माण के लिये पूरे प्रयास कर रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने कनिष्ठ अनुदेशकों के भर्ती नियमों में संशोधन को सही माना

जयपुर, 29 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के आईटीआई कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती- 2024 में राज्य सरकार की ओर से भर्ती नियमों में संशोधन करने को सही माना है। इसके साथ ही, अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को भर्ती नियमों में संशोधन का अधिकार है। वहीं, अदालत ने राज्य सरकार को यह भी छूट दी है कि वह 11 मार्च 2024 की भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार कनिष्ठ अनुदेशक के पद पर भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकती है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश कोमल

- जस्टिस इंद्रजीत सिंह व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने अभ्यर्थियों की याचिका खारिज की।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन, अमेरिका को चीते की खाल में भेड़िया क्यों कहता है

ट्रम्प की, ताकतवर प्रतिद्वंदी के सामने पीछे हटने की प्रवृत्ति, इस उपाधि में कुछ सत्यता का भान तो कराती है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मई। क्या आपने कभी ''टाको'' (टी.ए.सी.ओ.) या ''टाको ट्रेड'' के बारे में सुना है।

इसका अर्थ है ''ट्रम्प हमेशा पीछे हट जाते हैं।'' (ट्रंप ऑलवेज़ चिकन्स आउट)। यह एक उपाधि है जो चीन के नेटिज़न्स (इंटरनेट उपयोगकर्ताओं) ने उन्हें उस समय दी थी, जब वे चीन के साथ टैरिफ (शुल्क) युद्ध से डरते हुए नज़र आए। ट्रम्प ने चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ को 145 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही उसे चरणबद्ध तरीके से 30 प्रतिशत तक नीचे ले आए।

चीनी लोगों ने ट्रम्प की इन रियायतों को टैरिफ वॉर में चीन से टकराव के डर के रूप में देखा। इसके बाद खुद अमेरिका के प्रसिद्ध वॉल स्ट्रीट के लोगों ने उन्हें ''टाको ट्रेड'' की संज्ञा दी, यह कहते हुए कि अमेरिकी शेयर बाजार ट्रम्प की टैरिफ नीति पर बार-बार बदली जा रही स्थिति के कारण ऊपर-नीचे हो रहा है।

जब एक पत्रकार ने ओवल ऑफिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प से ही टाको प्रश्न पूछ लिया, तो वे पूरी तरह असहज हो गए। उन्होंने इसे ''सबसे घटिया सवाल'' बताया और उस पत्रकार से फिर कभी यह सवाल न पूछने को कहा। वे यह साबित करने का प्रयास कर रहे कि वे कायर नहीं हैं।

लेकिन इस सर्वव्यापी उपाधि का खंडन करने की कोशिश में ट्रंप बड़बोले साबित हुए हैं। एक ऐसे नेता, जो अपने वादों के अनुरूप कुछ कर नहीं पाए, चाहे वह चुनाव जीतने पर यूक्रेन युद्ध को एक दिन में समाप्त करने का दावा हो, या संघीय खर्च और बजट घाटा कम करने की बात, हर मुद्दे पर ट्रम्प की असलियत सामने आ चुकी है।

ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी, एलन मस्क, जिन्हें उन्होंने सरकारी दक्षता विभाग का प्रमुख नियुक्त किया था, उन्होंने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। मस्क ने सार्वजनिक रूप से ट्रम्प की विफलता की आलोचना करते हुए कहा कि वे संघीय खर्च को कम करने में असफल रहे।

एक टीवी साक्षात्कार में मस्क ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रंप का बहुप्रचारित ''बिग एक ब्यूटिफुल'' बिल, जिसमें कर कटौती और रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी शामिल है, वास्तव में ट्रम्प का पुराने वादों से पीछे हटने जैसा है। विधेयक अमेरिकी संघीय घाटे में 3.8 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी करेगा। यह एक बहुत बड़ा वित्तीय घाटा है, जबकि ट्रम्प ने इसे कम करने का वादा किया था।

मस्क ने कहा कि यह विधेयक या तो बड़ा हो सकता है या सुंदर, दोनों नहीं हो सकता, जैसा कि ट्रम्प ने कहा था। मस्क का मतलब साफ था: ट्रम्प अपने बड़े वित्तीय सुधारों से पीछे हट रहे हैं। ट्रंप के लिए यह सबसे क्रूर प्रहार है।

यूक्रेन युद्ध के मामले में भी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा उकसाये जाने के बावजूद, ट्रम्प ने उन्हें कठोर शब्दों में लताड़ने के बजाय नरमी बरती है। ट्रम्प शांति की बात कर रहे थे और यूक्रेन से अपने शांति फार्मूले के तहत

- अमेरिका ने पहले तो चीन से अमेरिका आने वाले सामान पर 145 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की और फिर जैसे-जैसे यह टैरिफ लगाने की तारीख नज़दीक आती गई, कई चरणों में अमेरिका ने एक के बाद टैरिफ घटाना शुरु किया और अब 30 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात चल रही है।
- इसी प्रकार पहले अमेरिका ने यूक्रेन वॉर का शांतिपूर्ण हल ढूढ़ने की दिशा में रूस पर सख्ती करने (आर्थिक प्रतिबंध आदि) की घोषणा करने का मानस दिखाया, पर, जब रूस ने इन धमकियों की परवाह नहीं करते हुए यूक्रेन में अपना आक्रामक रूप जारी ही नहीं रखा, बल्कि और तेज कर दिया, तो, अमेरिका ने फिर कमज़ोरी दिखाई और कहा, आर्थिक प्रतिबंध आदि कदम उठाने से दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों को धक्का लगेगा।
- इसी प्रकार भारत-पाक युद्ध में ट्रम्प यह दंभ भरते रहे कि व्यापार न करने की धमकी देकर उन्होंने दोनों देशों को ''सीज़फायर'' करवायी। पर, भारत के विदेश मंत्री ने भी कसर नहीं छोड़ी ट्रंप के इस दंभपूर्ण कथन को गलत बताने में।
- बार-बार दंभपूर्ण धमकियां देना व फिर पीछे हटना, क्या कायरता की निशानी नहीं। तो क्या चीन की उपाधि, वाकई में सटीक नहीं है?

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान हाई कोर्ट को तीन नये न्यायाधीश मिलेंगे

जयपुर, 29 मई। राजस्थान हाईकोर्ट को जल्दी ही तीन नए न्यायाधीश मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को वकील कोटे से नियुक्ति के लिए भेजे गए तीन नामों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके लिए कॉलेजियम की ओर से केन्द्र सरकार को

- वकील कोटे से अधिवक्ता बिपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित और रवि चिरानिया के नाम को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दी।

जल्दी ही अपनी सिफारिश भेजी जाएगी और राष्ट्रपति भवन से इनकी नियुक्ति वारंट जारी होने के बाद इनका शपथ समारोह होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से वकील कोटे से नियुक्ति के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता बिपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित और रवि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)